छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
निर्णय सुरक्षित: 05/03/2020
निर्णय सुनाया गया: 23/03/2020
रिट याचिका (सी) संख्या 194/2020

मेसर्स. शांति इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत पता क्लबपारा बोलनगीर उड़ीसा, कॉर्पोरेट कार्यालय शांति निवास अग्रसेन भवन के सामने कोरबा, छत्तीसगढ़, 495677, अपने निदेशक श्री रोहित अग्रवाल, उम्र लगभग 32, निवासी शांति निवास अग्रसेन भवन के सामने कोरबा, छत्तीसगढ़, 495677 के माध्यम से।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. एनटीपीसी लिमिटेड, अपने महाप्रबंधक के माध्यम से, जिसका पंजीकृत कार्यालय एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7, संस्थागत क्षेत्र, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 में है 2. अतिरिक्त महाप्रबंधक (सीएंडएम)/वरिष्ठ प्रबंधक (सीएंडएम) साझा सेवा केंद्र कोयला खनन मुख्यालय, एनटीपीसी लिमिटेड, कोयला खनन मुख्यालय रांची, चुटिया पुलिस स्टेशन के सामने, जिला रांची - 834001 झारखंड। 3. महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, तलाईपल्ली कोल माइनिंग प्रोजेक्ट लैलुंगा रोड, घरघोड़ा, जिला रायगढ़- 49611

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---- प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री विक्रम शर्मा, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों/कंपनी के लिए : श्री बी.डी.गुरु, अधिवक्ता।

माननीय श्री पी.आर. रामचंद्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री पार्थ प्रतिम साहू, न्यायाधीश

सी.ए.वी. निर्णय

श्री पी.आर. रामचंद्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश

1. प्रतिवादियों की ओर से मनमानी कार्रवाई, जिसमें याचिकाकर्ता को एल-1 रेटिंग दिए जाने के बावजूद, दिनांक 09.01.2020 के प्रदर्श पी/8 के माध्यम से बोली वापस लेने के लिए धमकाया और मजबूर किया गया, बयान राशि जमा (संक्षेप में 'ईएमडी') जब्त करने और याचिकाकर्ता को निविदा में जीएसटी दर का अलग से उल्लेख न करने के लिए भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट में डालने का प्रयास किया गया,हालांकि शेष तीन बोलीदाताओं के मामले में अलग व्यवहार किया गया और इसे उनकी पसंद की पार्टी को दिया गया, इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

2. प्रदर्श पी/2 निविदा आमंत्रण सूचना (संक्षेप में 'एनआईटी') 09.09.2019 को छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना के लिए दूसरे प्रतिवादी द्वारा जारी की गई थी, जो तीसरे प्रतिवादी के नियंत्रण में है। कोयला निकासी (खंड बी) के लिए सड़क और तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना (खंड सी) के लिए टाउनशिप पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए निविदा जारी की गई थी। उपरोक्त दोनों सड़कों के निर्माण का उद्देश्य काफी अलग था क्योंकि खंड बी सड़क का उपयोग कोयला निकासी के लिए किया जाना था जो टाउनशिप क्षेत्र के बाहर स्थित होगी और इसका उपयोग आम जनता भी कर सकती है, जबकि खंड सी सड़क का निर्माण टाउनशिप क्षेत्र के अंदर किया जाना था, जो पूरी तरह से एक निजी सड़क थी। वास्तव में, जब जुलाई, 2017 से माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को लागू किया गया था, तो कार्य अनुबंध होने के कारण देय करों की दर 18% (9% सीजीएसटी + 9% एसजीएसटी) निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात, जीएसटी परिषद की बैठक के अनुसरण में दिनांक 22.08.2017 के प्रदर्श पी/4 के अनुसार, दर को संशोधित किया गया, जिसमें सड़क के उद्देश्य के संदर्भ में कर की दर को अलग किया गया, जिसके कारण सेक्शन बी सड़क के निर्माण पर केवल 12% (6% सीजीएसटी + 6% एसजीएसटी) की कर देयता आनी थी, जबकि सेक्शन सी सड़क जो आंतरिक/टाउनशिप उद्देश्य के लिए थी, उस पर 18% (9% सीजीएसटी + 9% एसजीएसटी) की उच्च दर लागू होनी थी।

3. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जब 09.09.2019 को प्रदर्श पी/2 एनआईटी जारी की गई थी, तब प्रदर्श पी/4 संशोधित जीएसटी दर 22.08.2017 से लागू हो चुकी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

थी, लेकिन वेब पोर्टल में मौजूद फॉर्म के संबंधित कॉलम में जीएसटी दर का उल्लेख करने के लिए केवल एक कॉलम था। निविदा शर्तों में विशेष रूप से निर्धारित किया गया था कि अनुबंध की संभावित राशि (संक्षेप में 'पीएसी') 24,32,45,371.37 रुपये थी और बोलीदाता को दर "प्रतिशत" के हिसाब से उद्धृत करनी थी - सभी करों/शुल्कों सहित उच्च या निम्न।

4. बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों (संक्षेप में 'आईटीबी') के खंड 11.1.3.2 में प्रावधान है कि बोलीदाता (i) आधार मूल्य (सभी करों और शुल्कों आदि सहित, लेकिन जीएसटी को छोड़कर) और (ii) लागू जीएसटी% को उद्धृत करेगा, जैसा कि राशि के बिल में पूछा गया है। आईटीबी के खंड 11.3 में प्रावधान है कि यदि बोली किसी भी तरह से दोषपूर्ण थी, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाना था, जिससे बोली वापस लेने के मामले में वारंट के अनुसार किसी भी ईएमडी की जब्ती नहीं होगी। आईटीबी के खंड 12.3 के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि उद्धृत की जाने वाली दर जीएसटी को छोड़कर थी, क्योंकि जीएसटी को अलग से उद्धृत किया जाना था। आईटीबी के खंड 12.4 के तहत, यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया था कि जीएसटी का भुगतान नियोक्ता की देयता (पुरस्कार देने वाले की देयता) होगी।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. करों, शुल्कों, लेवी आदि से निपटने वाले अनुबंध की सामान्य शर्तों (संक्षेप में 'जीसीसी') के खंड 26 में विशेष रूप से जोर दिया गया है (खंड 26.2 के तहत) कि जीएसटी का भुगतान करना नियोक्ता का कर्तव्य होगा। यह वस्तुतः खंड 26.1 के तहत शर्त का अपवाद है जो ठेकेदार पर सभी करों, शुल्कों, लेवी आदि को पूरा करने का दायित्व डालता है।

6. आईटीबी का खंड 14.5 निम्नलिखित प्रभाव के लिए है: "14.5 बोली सुरक्षा नियोक्ता को किसी भी नोटिस या नुकसान के सबूत के बिना निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी में भी जब्त कर ली जाएगी: (ए) यदि बोलीदाता बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है या बदलता है। (ख) यदि सफल बोलीदाता आईटीबी उप-धारा 23.2 के अनुसार अपनी बोली मूल्य में सुधार को स्वीकार नहीं करता है। (ग) यदि सफल बोलीदाता नियोक्ता को किसी भी लागत के बिना, बोली में कहीं भी पाए गए बोली दस्तावेजों में किसी भी विचलन को वापस लेने से इनकार करता है। (घ) यदि सफल बोलीदाता अनुबंध के

पुरस्कार को स्वीकार करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विफल रहता है या आईटीबी खंड 27 के अनुसार आवश्यक अनुबंध प्रदर्शन सुरक्षा प्रस्तुत करने में विफल रहता है। (ङ) यदि बोलीदाता / उसका प्रतिनिधि एनटीपीसी की धोखाधड़ी रोकथाम नीति के अनुसार इस अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय कोई धोखाधड़ी करता है। (च) यदि बोलीदाता को सत्यनिष्ठा संधि की धारा 3 और 4 के अनुसार बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जाता है।

7. आईटीबी के खंड 23.2.3 के तहत, यदि उद्धृत दर दोषपूर्ण थी, तो नियोक्ता के लिए शेष राशि को जोड़ना तथा किसी भी तरह से उद्धरण को कम नहीं करना खुला था। आईटीबी के खंड 23.3 में यह और स्पष्ट किया गया है कि यदि उद्धृत राशि दोषपूर्ण है, तो बोली मूल्य तय करने के लिए इसका उचित मूल्यांकन किया जाना था तथा एल-1 बोलीदाता की पहचान करने के लिए मूल्यांकित बोली मूल्य घोषित किया जाना था। ऐसा बोलीदाता द्वारा खुद को एल-1 बोलीदाता होने का दावा करने के लिए कम राशि उद्धृत करने के किसी भी अवसर से बचने के लिए किया गया था। इसी तरह, यदि कोई बोलीदाता जीएसटी की उच्च दर उद्धृत करता है, चूंकि जीएसटी की दर वैधानिक है, केवल अधिसूचित दर का दावा किया जा सकता है या आईटीबी के खंड 12.4 के तहत दायित्व के आधार पर पुरस्कारकर्ता द्वारा भुगतान किया जा सकता है (कि जीएसटी को संतुष्ट करने का दायित्व हमेशा पुरस्कारकर्ता/नियोक्ता के लिए होगा)। इसके अलावा, जीएसटी अधिनियम की धारा 9, आईटीबी के खंड 12.4 के साथ पढ़ी गई स्पष्ट रूप से सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(119) (जिसमें निर्माण शामिल है) के साथ पढ़ी गई "कार्य अनुबंध" के पुरस्कारकर्ता/नियोक्ता के लिए ठेकेदार के पुरस्कारकर्ता पर जीएसटी को संतुष्ट करना अनिवार्य बनाता है, चाहे दर कुछ भी हो। इसका आशय यह है कि चाहे निविदा में जीएसटी की दर बताई गई हो या कोई गलत दर बताई गई हो, बोली के मूल्यांकन के संबंध में इसका कोई असर नहीं हो सकता, खासकर तब जब बोली का मूल्यांकन करने का अधिकार अनुबंध देने वाले को आईटीबी के खंड 23.2.3 के साथ खंड 23.3 के अनुसार निहित हो। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले का विश्लेषण उपरोक्त पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, दिनांक 11.09.2014 के प्रदर्श पी/4 के अनुसार निर्धारित विभिन्न दरों के कारण। 22.08.2017 (संशोधित दर) अनुबंध पी/2 एनआईटी के सार्वजनिक उद्देश्य (धारा-बी) वाली सड़कों के निर्माण के लिए 12% की कम कर दर और अनुबंध पी/2 एनआईटी के आंतरिक/निजी उद्देश्य (धारा-सी) के लिए सड़कों के निर्माण के संबंध में 18% की उच्च कर दर का प्रावधान करते हुए, और चूंकि निविदा की शर्तों में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि बोली राशि का उद्धरण जीएसटी को छोड़कर किया जाना था और आगे यह कि जीएसटी की संतुष्टि हमेशा विजेता/नियोक्ता की देयता होगी, याचिकाकर्ता ने बोली 18,24,58,353.06 रुपये पर उद्धृत की और जीएसटी की दर का उल्लेख करने वाला कॉलम खाली छोड़ दिया गया। उपरोक्त अनुसार निविदा प्रस्तुत करने पर, याचिकाकर्ता को दिनांक 27.12.2019 का अनुलग्नक पी/5 भेजा गया, जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता ने जीएसटी की दर का उल्लेख नहीं किया है, रु. 18,24,58,353.06 को जीएसटी सहित माना गया और इसलिए जीएसटी घटाकर उद्धरण को 15,46,25,723/- तक लाया गया; जिसे अनुमानित दर रु. 24,32,45,371.32 के 36.43% से कम बताया गया और इसलिए इसे 'असामान्य रूप से कम दर' के रूप में ब्रांड किया गया। बोलीदाताओं (आईटीबी) को दिए गए विशिष्ट निर्देशों के आधार पर, याचिकाकर्ता को कार्य दिए जाने की स्थिति में 2,21,54,912 रुपये की अतिरिक्त प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त प्रदर्शन सुरक्षा वचनबद्धता प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उक्त संचार प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता ने प्रदर्श पी/7 उत्तर दिनांक 08.01.2020 को प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा जीएसटी को छोड़कर उद्धृत बोली 18,24,58,353.06 रुपये थी, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विवरण भी दिए गए। हालाँकि, उक्त उत्तर पर कोई ध्यान दिए बिना, याचिकाकर्ता को प्रदर्श पी/8 दिनांक 09.01.2020 भेजा गया, जिसमें याचिकाकर्ता को बलपूर्वक कार्रवाई करने और ईएमडी जब्त करने और भविष्य के लेन-देन में भाग लेने से याचिकाकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने के इरादे से बोली वापस लेने के लिए मजबूर करने की धमकी दी गई। इससे याचिकाकर्ता को प्रदर्श पी/8 को चुनौती देने और प्रतिवादियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्रवाई को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. जब मामला 15.01.2020 को इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया, तो प्रतिवादियों को तत्काल नोटिस जारी किया गया, साथ ही सुनवाई की अगली तारीख तक ईएमडी जब्त करने के संबंध में यथास्थिति का अंतरिम आदेश भी दिया गया, जिसे आगे बढ़ाया जाना था। नोटिस प्राप्त होने पर, प्रतिवादियों ने उपस्थिति दर्ज की और प्रदर्श पी/8 जारी करने में अपनी कार्रवाई को बनाए रखने की मांग करते हुए जवाब दाखिल किया, क्योंकि याचिकाकर्ता इस संबंध में स्पष्ट शर्त के बावजूद जीएसटी की दर उद्धृत करने में विफल रहा था। उक्त परिस्थिति में, जीएसटी को उद्धृत दर से अलग करना पड़ा, इस प्रकार उद्धरण 18,24,58,353.06 रुपये से घटकर 18,24,58,353.06 रुपये हो गया। 15,46,25,723/- जो अनुमानित कीमत (असामान्य रूप से कम दर) से बहुत कम था, जिसके कारण उसमें उल्लिखित अन्य परिणाम हुए। यह भी तर्क दिया गया है कि रिट याचिका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण बनाए रखने योग्य नहीं है, क्योंकि निविदा झारखंड राज्य के रांची से जारी की गई है। प्रतिवादियों ने आगे तर्क दिया कि निविदा में निर्धारित शर्तों को अन्य प्रतिभागियों द्वारा सही ढंग से समझा गया है जिन्होंने जीएसटी को अलग से उद्धृत करते हुए अपनी निविदाएं प्रस्तुत की हैं और रिट याचिका को केवल किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण खारिज किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में उठाए गए विवादों को वस्तुतः दोहराते हुए और प्रतिवादियों द्वारा दायर रिटर्न की सामग्री का खंडन करने की मांग करते हुए एक प्रतिउत्तर दायर किया है।

11. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री विक्रम शर्मा और प्रतिवादी-कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री बी.डी.गुरु को सुना।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रदर्श पी/6 के संदर्भ में बताया कि यह याचिकाकर्ता द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत बोली का स्क्रीन शॉट है, जिसमें कॉलम संख्या 6 में 24,32,45,371.37 रुपए की अनुमानित कीमत स्पष्ट रूप से दिखाई गई है, याचिकाकर्ता द्वारा कॉलम संख्या 9 में कम यानी माइनस में दी गई प्रविष्टि और कॉलम संख्या 13 में अनुमानित लागत का 24.99% के रूप में पेश किया गया उद्धरण, जो कि जीएसटी के बिना

है। कॉलम संख्या 18 (जीएसटी की दर के संबंध में) को खाली छोड़ दिया गया था, जिसे प्रदर्श पी/5 पत्र में भी स्वीकार किया गया है। कॉलम संख्या 54 में याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत राशि 18,24,58,353.06 रुपये दर्शाई गई है, हालांकि प्रतिवादियों द्वारा वेब पोर्टल पर दिए गए उक्त कॉलम में शीर्षक को प्रीमियम/छूट और जीएसटी सहित राशि के रूप में वर्णित किया गया है। प्रतिवादियों के अनुसार और निविदा शर्तों में अधिसूचित अनुसार, उद्धरण में कभी भी जीएसटी शामिल नहीं किया जाना था और जीएसटी की दर कॉलम संख्या 18 के तहत अलग से दी जानी थी। यह स्थिति होने के कारण, प्रतिवादियों के लिए याचिकाकर्ता की बोली राशि की गणना करने के लिए 18,24,58,353.06 रुपये की बोली से जीएसटी को कम करना कभी भी संभव नहीं था और आईटीबी की धारा 23.3 के तहत विशिष्ट खंडों के आधार पर, आईटीबी की धारा 23.2.3 के साथ पढ़ा जाए, यदि उद्धृत राशि किसी भी तरह से दोषपूर्ण थी, तो इसे जोड़ा जाना था और एल-1 बोलीदाता की पहचान करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा मूल्यांकित बोली मूल्य की गणना की जानी थी। निविदा शर्तों में बोली राशि को कम करने का प्रावधान नहीं है, और इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा की गई कार्रवाई सभी मामलों में गलत और अवैध थी। विद्वान वकील ने कहा कि यदि बोली गलत थी, स्वीकार्य नहीं थी या किसी भी तरह से दोषपूर्ण थी, तो वे इसे आईटीबी के खंड 11.3 के आधार पर अस्वीकार कर सकते थे; ऐसी स्थिति में, ईएमडी जब्त करने या याचिकाकर्ता को काली सूची में डालने के रूप में कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं होना चाहिए था। बोली राशि में 'अनधिकृत कटौती' के संदर्भ में, प्रतिवादी प्रदर्श पी/5 के माध्यम से याचिकाकर्ता पर बोली वापस लेने का आग्रह कर रहे थे, ताकि वे ईएमडी जब्त कर सकें और याचिकाकर्ता को काली सूची में डाल सकें, जो कि अपने आप में गलत और अवैध है।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में रिट याचिका की स्थिरता के बारे में उठाई गई आपत्ति का कोई आधार नहीं है क्योंकि इस न्यायालय की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(2) के तहत विशिष्ट प्रावधान के आधार पर काफी व्यापक है जो यह निर्धारित करता है कि खंड (1) के तहत न्यायालय की किसी भी सरकार, प्राधिकरण या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग इस न्यायालय द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए भी किया जा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सकता है जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए कार्रवाई का कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है, भले ही ऐसी सरकार/प्राधिकरण की सीट या ऐसे व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों के भीतर न हो। विद्वान वकील ने कहा कि प्रदर्श पी/2 एनआईटी तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना के लिए सड़कों के निर्माण के लिए जारी की गई थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित है। उपरोक्त सड़कों का निर्माण राज्य में आम जनता के लाभ के लिए किया गया था और विशेष रूप से रायगढ़ में और इसके अलावा प्रतिवादियों का छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक परियोजना कार्यालय भी था। यह स्थिति होने के कारण, कार्रवाई का कारण मुख्य रूप से या कम से कम आंशिक रूप से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में उत्पन्न हुआ था और इस मामले से निपटने के लिए इस न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार है। यह भी बताया गया है कि, हालांकि एनआईटी में एक खंड है जिसमें कहा गया है कि सभी विवाद रांची के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे, यह तभी लागू हो सकता है जब क्षेत्राधिकार को उस स्थान तक सीमित करते हुए एक समझौता किया जाता है (जब कार्रवाई/विवाद का कारण अलग-अलग स्थानों पर उत्पन्न हो रहा हो, जो अलग-अलग न्यायालयों को क्षेत्राधिकार प्रदान करता है)। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1980 की धारा 20 (सी) का संदर्भ दिया गया है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जब तक कोई समझौता निष्पादित नहीं हुआ है और वह चरण अभी भी पूरा नहीं हुआ है, इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी भी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। ए.बी.सी. लैमिनार्ट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम ए.पी. एजेंसियां, सेलम; {(1989) 2 एससीसी 163, पैराग्राफ 13 से 17} में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर भरोसा किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. एबीसी लेमिनार्ट प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में दिए गए निर्णय के पैराग्राफ 15 को आसान संदर्भ के लिए उद्धृत करना उचित होगा: “15. अनुबंध के मामले में विभिन्न प्रकार के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। अनुबंध के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमे में कार्रवाई का कारण अनुबंध का निर्माण और उसका उल्लंघन है, इसलिए मुकदमा या तो उस स्थान पर दायर किया जा सकता है जहां अनुबंध किया गया था या उस स्थान पर जहां इसे निष्पादित किया जाना चाहिए था और उल्लंघन हुआ था। अनुबंध का निर्माण कार्रवाई के कारण का हिस्सा है। इसलिए, अनुबंध पर मुकदमा उस स्थान पर दायर किया जा सकता है जहां इसे

बनाया गया था। अनुबंध के निर्माण के स्थान का निर्धारण अनुबंध के कानून का हिस्सा है। लेकिन किसी विशेष स्थान पर प्रस्ताव करना अनुबंध के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति के मुकदमे में कार्रवाई का कारण नहीं बनता है। आम तौर पर, किसी प्रस्ताव की स्वीकृति और उसकी सूचना के परिणामस्वरूप अनुबंध होता है और इसलिए उस न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में स्वीकृति की सूचना दी गई थी। अनुबंध का निष्पादन कार्रवाई के कारण का हिस्सा है और उल्लंघन के संबंध में मुकदमा हमेशा उस स्थान पर दायर किया जा सकता है जहां अनुबंध का निष्पादन किया जाना चाहिए था या उसका निष्पादन पूरा हो जाना चाहिए था। यदि अनुबंध का निष्पादन उस स्थान पर किया जाना है जहां इसे बनाया गया है, तो अनुबंध पर मुकदमा वहीं दायर किया जाना चाहिए और कहीं और नहीं। एजेंसी कार्रवाइयों के लिए मुकदमों में कार्रवाई का कारण उस स्थान पर उत्पन्न होता है जहां एजेंसी का अनुबंध किया गया था या वह स्थान जहां कार्रवाई की जानी है और एजेंट द्वारा भुगतान किया जाना है। कार्रवाई के कारण का हिस्सा तब उत्पन्न होता है जब अनुबंध के तहत पैसा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से देय होता है। अनुबंध के अस्वीकार होने की स्थिति में, वह स्थान जहां अस्वीकार प्राप्त होता है, वह स्थान है जहां मुकदमा होगा। यदि किसी अनुबंध को कार्रवाई के कारण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उस न्यायालय को क्षेत्राधिकार दिया जाता है, जहां मुकदमा दायर किया गया है और वह अनुबंध अमान्य पाया जाता है, तो कार्रवाई के कारण का ऐसा हिस्सा गायब हो जाता है। उपरोक्त कुछ जोड़ने वाले कारक हैं। इसी तरह, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के चुनाव आयोग बनाम साका वेंकट राव {AIR 1953 SC 210, पैराग्राफ 6 और 7} में पारित फैसले पर भी भरोसा किया जाता है, इसके अलावा (अनुमति के साथ) कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मिलिपोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत सरकार और अन्य {AIR 2002 कर्नाटक 280, पैराग्राफ 9, 11, 13, 14 और 15} में पारित फैसले का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया गया है।

15. इसमें शामिल योग्यता के संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सार्वजनिक उद्देश्य (धारा बी - 12%) और आंतरिक/निजी उद्देश्य (धारा सी - 18%) के लिए सड़कों के निर्माण के संबंध में 22.08.2017 को लाए गए और अधिसूचित प्रदर्श पी/4

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

संशोधन के आधार पर जीएसटी की दो अलग-अलग दरों के अस्तित्व को प्रतिवादियों द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। चूंकि प्रदर्श पी/4 निविदा जारी करने की तिथि यानी 09.09.2019 को क्षेत्र को नियंत्रित करता था, इसलिए प्रतिवादियों को स्थिति पर ध्यान देना चाहिए था और वेब पोर्टल में विभिन्न दरों के साथ प्रविष्टियां करने के लिए उचित कॉलम प्रदान करना चाहिए था, जो निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं है। अन्य प्रतिभागियों के मन में भी भ्रम था, जैसा कि प्रतिभागियों द्वारा उद्धृत प्रदर्श आर/1 मूल्य बोलियों से पता चलता है। कॉलम नंबर 18 में सुनील कुमार अग्रवाल नाम के बोलीदाता द्वारा उद्धृत जीएसटी की दर केवल '12%' है, जबकि आर.के. ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नाम के एक अन्य बोलीदाता ने दर '18%' बताई है। सुनील कुमार अग्रवाल द्वारा 'सुनील कुमार अग्रवाल एलएलपी' (सीमित देयता भागीदारी) के रूप में एक अलग क्षमता में उद्धृत बोली में जीएसटी की दर '18%' बताई गई है। इसका मतलब है कि किसी अन्य बोलीदाता ने सड़कों के निर्माण के संबंध में सही या अलग से दर नहीं बताई थी और इसी भ्रम के कारण याचिकाकर्ता ने कॉलम नंबर 18 (जीएसटी की दर का उल्लेख करने के लिए प्रदान किया गया) को खाली छोड़ दिया। यह और भी अधिक था, क्योंकि जीएसटी अधिनियम की धारा 9 के साथ आईटीबी के खंड 12.4 के आधार पर जीएसटी की संतुष्टि नियोक्ता की देयता थी; जिसके कारण बोलीदाता द्वारा दर का उल्लेख करना महत्वहीन था। दर जो भी हो, उसे पुरस्कार देने वाले को संतुष्ट करना था और इस प्रकार, बोलीदाता द्वारा किसी विशेष दर का उल्लेख करने से कभी भी किसी भी तरह से संतुलन नहीं बिगड़ेगा, जहाँ तक उसकी बोली (जीएसटी को छोड़कर दी जाने वाली निर्धारित) का संबंध है। सी.ए. जॉर्ज बनाम केरल राज्य {एआईआर ऑनलाइन 2019 केर 713, पैराग्राफ 12, 13 और 14} में रिपोर्ट की गई केरल उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि यदि कर की दर कॉलम में नहीं बताई गई है और यदि बोली राशि तदनुसार उद्धृत की गई है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि बोली राशि कर/जीएसटी सहित है।

16. दोनों पक्षों को सुनने के बाद, हम पाते हैं कि रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के संदर्भ में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों में काफी दम है। जहां तक इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मूल रूप से प्रदर्श पी/3 के अनुसार अधिसूचित जीएसटी दर को

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

संशोधित कर दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रदर्श पी/4 दिनांक 22.08.2017 के अनुसार (सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सड़कों के निर्माण के लिए 12% की कम दर निर्धारित करना (धारा-बी) और आंतरिक/निजी उद्देश्य के लिए सड़कों के निर्माण के लिए 18% की उच्च दर निर्धारित करना (धारा-सी), उत्तरदाताओं के लिए 09.09.2019 को जारी प्रदर्श पी/2 निविदा में अलग-अलग कॉलम प्रदान करना अनिवार्य था, जब प्रदर्श पी/4 अधिसूचना क्षेत्र को नियंत्रित कर रही थी। इसके अलावा, जीएसटी अधिनियम की धारा 9 के साथ आईटीबी के खंड 12.4 के तहत स्पष्ट शर्तों के आधार पर, जीएसटी का भुगतान पुरस्कारकर्ता की देयता थी और इसलिए, जीएसटी की दर का उल्लेख या गैर-उल्लेख कोई महत्व नहीं रखता था क्योंकि यह एक 'स्थिर आंकड़ा' है जिसके संबंध में बोलीदाता या पुरस्कार देने वाले द्वारा कोई परिवर्तन नहीं सोचा जा सकता है। सबसे बढ़कर, यदि कोई गलती थी या बोली देय शुल्कों/करों के संदर्भ में उचित राशि उद्धृत न करने के कारण दोषपूर्ण थी, तो प्रतिवादियों के लिए आईटीबी के खंड 23.2.3 के साथ खंड 23.3 के अनुसार बोली का पुनर्मूल्यांकन करना पूरी तरह से खुला था ताकि वास्तविक उद्धरण निकाला जा सके और एल-1 बोलीदाता की पहचान की जा सके। जाहिर है, इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर कोई ध्यान दिए बिना, कार्यवाही को जल्दबाजी में आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, प्रदर्श पी/8 जारी करके; वस्तुतः प्रदर्श पी/5 के जवाब में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदर्श पी/7 के माध्यम से उठाई गई आपत्ति/स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना। हमारा विचार है कि रिट याचिका में आरोपित दिनांक 09.01.2020 के प्रदर्श पी/8 आदेश/कार्यवाही कायम रखने योग्य नहीं है और इसलिए इसे रद्द किया जाता है।

17. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, प्रदर्श पी/2 एनआईटी में निहित सक्षम करने वाले खंडों के मद्देनजर, प्रतिवादियों के लिए याचिकाकर्ता सहित सभी प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत बोली का पुनर्मूल्यांकन करना और वास्तविक बोली राशि की गणना करना अभी भी खुला है, यदि जीएसटी को भी बोली के हिस्से के रूप में माना जाता है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता या ऐसे अन्य बोलीदाता द्वारा उद्धृत बोली से जीएसटी घटाने के बजाय इसे जोड़ा जाता है। उपर्युक्त के अनुसार पुनर्मूल्यांकन करने के बाद, बोली कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जा सकता है, सफल बोलीदाता की पहचान की जा सकती है और कार्य को तदनुसार प्रदान किया जा सकता है; कानून के अनुसार अन्य आवश्यकताओं की संतुष्टि के अधीन। चूंकि देय 'कर की दर' और

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नियोक्ता/पुरस्कारदाता की देयता के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है, इसलिए प्रतिवादियों के लिए याचिकाकर्ता सहित बोलीदाताओं द्वारा दिए गए उद्धरणों पर विचार करना खुला है (इसे जीएसटी को छोड़कर मानते हुए) क्योंकि किसी ने भी यह दावा नहीं किया है कि इसमें जीएसटी शामिल है और आगे जब निविदा की शर्तों में यह निर्धारित किया गया है कि इसमें जीएसटी शामिल नहीं होना चाहिए। प्रतिवादी-कंपनी के लिए भी यह खुला है कि यदि वे चाहें तो वे पुनः निविदा के लिए जा सकते हैं, इस संबंध में उचित स्पष्टीकरण देते हुए और कर की दर के संदर्भ में विभिन्न कार्यों (धारा-बी और धारा-सी को अलग-अलग) को दिखाते हुए वेब पोर्टल में प्रविष्टियाँ करने के लिए आवश्यक कॉलम प्रदान करते हुए।

18. रिट याचिका स्वीकार की जाती है। कोई व्यय नहीं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(पी०आर० रामचंद्र मेनन)
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
(पार्थ प्रतीम साहू)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**